



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-12]

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2011 ई0 (चैत्र 12, 1933 शक सम्वत्)

[संख्या-14

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द्रा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	137-138	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	75-79	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	17-22	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	1-3	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड-पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड

(अधिष्ठान अनुभाग)

अधिसूचना/प्रकीर्ण

15 मार्च, 2011 ई0

संख्या 1293/वि0स0/423/अधि0/2011-"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अन्तर्गत प्रख्यापित उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की नियमावली, 2011 के नियम-3 के खण्ड (ज) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी तथा अन्य (2006) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में वर्णित सम्यक् प्रक्रिया के अनुसार न की गई नियुक्तियों के एक बार किये जाने वाले समेकन के सिद्धान्त को आधार मानते हुए, मैं, हरबंस कपूर, अध्यक्ष विधान सभा, उत्तराखण्ड व्यापक जनहित में उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय में उपरोक्त नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त के इतर समस्त तदर्थ रूप से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अथवा पदोन्नत द्वारा नियुक्त कर्मचारिवृन्द की सेवाओं के विनियमितीकरण हेतु निम्नवत् एक चयन समिति का गठन करता हूँ :-

1-श्री हरीश चन्द्र जोशी, अपर सचिव।

2-श्री विष्णु चक्र थपलियाल, संयुक्त सचिव।

3-श्री जगदीश चन्द्र, संयुक्त सचिव।

(क) यह समिति उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् विधान सभा सचिवालय में वर्षानुवर्ष सृजित एवं उपलब्ध विभिन्न संवर्गों के अनुसचिव स्तर तक के पदों के सापेक्ष तदर्थ रूप से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अथवा पदोन्नत द्वारा नियुक्त कर्मचारिवृन्द के सम्बन्धित पदों पर की गयी संतोषजनक सेवाओं, कार्य, आचरण एवं व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए विनियमितीकरण के सम्बन्ध में संस्तुति करेगी।

(ख) समिति शासन द्वारा समय-समय पर सेवाओं में विभिन्न संवर्गों हेतु आरक्षण सम्बन्धी निर्गत शासनादेशों के आलोक में विनियमितीकरण हेतु संस्तुतियां करेगी।

(ग) जहां समिति का यह सामधान हो जाय कि सम्बन्धित कर्मचारी विधान सभा सचिवालय की गरिमा एवं उत्कृष्टता के दृष्टिगत उपयुक्त नहीं है, ऐसे कर्मचारियों का विनियमितीकरण रोके जाने की संस्तुति की दशा में पृथक से सकारण टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(घ) नियमावली के प्रख्यापित होने से पूर्व सीधी भर्ती के पदों पर तदर्थ नियुक्त कर्मचारीगण यदि वे नियमावली में वर्णित शैक्षिक योग्यतायें/अनुभव धारक न हो तो, उन्हें जिन स्थितियों में तत्समय की परिस्थितियों के अनुरूप नियुक्त किया गया है, के आधार पर विनियमितीकरण अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदन के उपरान्त सम्पादित किया जायेगा।

(झ) यह समिति तीन माह की अवधि में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी।

हरबंस कपूर,

अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

महेश चन्द्र,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2011 ई0 (चैत्र 12, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 24, 2011

No. 15/XIV-04/Admin. A/2008--Ms. Pratibha Tiwari, Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 28 days w.e.f. 15.01.2011 to 11.02.2011 with permission to suffix 12.02.2011 and 13.02.2011 as 2nd Saturday and Sunday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection).

March 07, 2011

No. 19/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to the Notification No. 335/XXX-1-11-26(15)/2010, dated 04.03.2011 of Government of Uttarakhand, Ms. Rinki Sahni is posted as Judicial Magistrate-II, Dehradun in the vacant Court. She is appointed in the said Court U/S 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

March 07, 2011

No. 20/UHC/Admin. A/2011--Ms. Rajni Shukla, 2nd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar shall be 1st Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar in the vacant Court.

March 07, 2011

No. 21/UHC/Admin. A/2011--Sri Rahul Kumar Srivastav, 4th Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar shall be 2nd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar vice Ms. Rajni Shukla.

March 07, 2011

No. 22/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to the Notification No. 335/XXX-1-11-26(15)/2010, dated 04.03.2011 of Government of Uttarakhand, Ms. Shivani Pashbola is posted as 3rd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar in the vacant Court.

March 07, 2011

No. 23/UHC/Admin. A/2011--Pursuant to the Notification No. 335/XXX-1-11-26(15)/2010, dated 04.03.2011 of Government of Uttarakhand, Sri Ravi Prakash is posted as 4th Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar vice Sri Rahul Kumar Srivastav.

March 07, 2011

No. 24/UHC/Admin. A/2011—Pursuant to the Notification No. 335/XXX-1-11-26(15)/2010, dated 04.03.2011 of Government of Uttarakhand, Sri Mohammad Yaqub is posted as 2nd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, Distt. Nainital in the vacant Court.

March 07, 2011

No. 25/UHC/Admin. A/2011—Pursuant to the Notification No. 335/XXX-1-11-26(15)/2010, dated 04.03.2011 of Government of Uttarakhand, Sri Shajad Ahmad Wahid is posted as 1st Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, Distt. Udhamasingh Nagar in the vacant Court.

March 07, 2011

No. 26/UHC/Admin. A/2011—Pursuant to the Notification No. 335/XXX-1-11-26(15)/2010, dated 04.03.2011 of Government of Uttarakhand, Ms. Ekta Mishra is posted as 2nd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, Distt. Udhamasingh Nagar in the vacant Court.

March 07, 2011

No. 27/UHC/Admin. A/2011—Pursuant to the Notification No. 335/XXX-1-11-26(15)/2010, dated 04.03.2011 of Government of Uttarakhand, Sri Rajeev Dhawan is posted as 3rd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, Distt. Udhamasingh Nagar in the vacant Court.

By Order of the Court,

Sd/-

U. C. DHYANI,
Registrar General..

March 08, 2011

No. 28/XIV-17/Admin. A/2008—Sri Shivakant Dwivedi, Assistant Director, Uttarakhand Judicial And Legal Academy, Bhowali, District Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 14.02.2011 to 01.03.2011 with permission to prefix 12.02.2011 and 13.02.2011 as 2nd Saturday and Sunday holidays and to suffix 02.03.2011 as Mahashivratri holiday.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

March 09, 2011

No. 29/UHC/XIV/33/Admin.A--Sri D.P. Gairola, District & Sessions Judge, Pithoragarh, is hereby sanctioned medical leave for 21 days w.e.f. 05.02.2011 to 25.02.2011.

March 09, 2011

No. 30/XIV/37/Admin. A/2008—Sri Arun Vohra, Civil Judge (Jr. Div.), Pauri Garhwal, is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 14.02.2011 to 26.02.2011 with permission to prefix 12.02.2011 and 13.02.2011 as 2nd Saturday and Sunday holidays and to suffix 27.02.2011 as Sunday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

March 10, 2011

No. 31/UHC/Admin. A/2011--Sri Vivek Bharti Sharma, Addl. District Judge/1st F.T.C., Nainital shall be the Additional District & Sessions Judge, Nainital in the vacant Court.

March 10, 2011

No. 32/UHC/Admin. A/2011--Sri Rajendra Joshi, Addl. District Judge/1st F.T.C., Roorkee, Distt. Hardwar is transferred & posted as Additional District Judge/1st F.T.C., Nainital *vice* Sri Vivek Bharti Sharma.

March 10, 2011

No. 33/UHC/Admin. A/2011--Sri Srikant Pandey, Addl. District Judge/2nd F.T.C., Dehradun is transferred & posted as Addl. District Judge/1st F.T.C., Roorkee, Distt. Hardwar *vice* Sri Rajendra Joshi.

March 10, 2011

No. 34/UHC/Admin. A/2011--Smt. Neelam Ratra, Chief Judicial Magistrate, Hardwar is transferred & posted as Civil Judge (S.D.), Kotdwar, Distt. Pauri Garhwal *vice* Sri Sujeet Kumar.

March 10, 2011

No. 35/UHC/Admin. A/2011--Sri Sujeet Kumar, Civil Judge (S.D.), Kotdwar, Distt. Pauri Garhwal is transferred & posted as Civil Judge (S.D.), Nainital in the vacant Court.

March 10, 2011

No. 36/UHC/Admin. A/2011--Sri Mahesh Chandra Kaushiwa, 1st Additional Civil Judge (S.D.), Dehradun is transferred & posted as Chief Judicial Magistrate, Rudrapur in the vacant Court.

March 10, 2011

No. 37/UHC/Admin. A/2011--Sri Om Kumar, Civil Judge (S.D.), Rishikesh, Distt. Dehradun is transferred & posted as Civil Judge (S.D.), Pithoragarh in the vacant Court.

March 10, 2011

No. 38/UHC/Admin. A/2011--Sri Ambika Pant, Judicial Magistrate, Hardwar is transferred & posted as Asstt. Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, Nainital *vice* Sri Shiva Kant Dwivedi.

March 10, 2011

No. 39/UHC/Admin. A/2011--Sri Pradeep Kumar Mani, Addl. Civil Judge (J.D.), Khatima, Distt. Udham Singh Nagar is transferred & posted as Civil Judge (J.D.), Vikasnagar, Distt. Dehradun *vice* Sri Sudhir Kumar Singh.

March 10, 2011

No. 40/UHC/Admin. A/2011--Sri Arvind Nath Tripathi, Judicial Magistrate-I, Dehradun is transferred & posted as Judicial Magistrate, Roorkee, Distt. Hardwar *vice* Sri Mukesh Chandra Arya. He is appointed in the said Court u/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

March 10, 2011

No. 41/UHC/Admin. A/2011--Ms. Pratibha Tiwari, Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar is transferred & posted as Judicial Magistrate, Hardwar *vice* Sri Ambika Pant. She is appointed in the said Court u/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

March 10, 2011

No. 42/UHC/Admin. A/2011--Sri Rajoo Kumar Srivastava, Civil Judge (J.D.), Ramnagar, Distt. Nainital is transferred & posted as Civil Judge (J.D.), Hardwar *vice* Ms. Reena Negi.

March 10, 2011

No. 43/UHC/Admin. A/2011--Sri Kuldeep Sharma, Civil Judge (J.D.), Khatima, Udham Singh Nagar is transferred & posted as Civil Judge (J.D.), Ramnagar, Distt. Nainital *vice* Sri Rajoo Kumar Srivastava.

March 10, 2011

No. 44/UHC/Admin. A/2011--Ms. Reena Negi, Civil Judge (J.D.), Hardwar is transferred & posted as Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar *vice* Ms. Pratibha Tiwari. She is appointed in the said Court u/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

March 10, 2011

No. 45/UHC/Admin. A/2011--Sri Chandramani Rai, Civil Judge (J.D.), Kashipur, Udham Singh Nagar is transferred & posted as 1st Addl. Civil Judge (J.D.), Hardwar vice Ms. Rajni Shukla.

March 10, 2011

No. 46/UHC/Admin. A/2011--Sri Ritesh Kumar Srivastava, Civil Judge (J.D.), Almora is transferred & posted as Judicial Magistrate-I, Dehradun vice Sri Arvind Nath Tripathi. He is appointed in the said Court u/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

March 10, 2011

No. 47/UHC/Admin. A/2011--Sri Ashutosh Kumar Mishra, Civil Judge (J.D.), Tehri Garhwal is transferred & posted as Civil Judge (J.D.), Khatima, Distt. Udham Singh Nagar vice Sri Kuldeep Sharma.

March 10, 2011

No. 48/UHC/Admin. A/2011--Sri Shiva Kant Dwivedi, Asstt. Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, Nainital is repatriated & posted as Civil Judge (J.D.), Dehradun vice Smt. Geeta Châuhan.

March 10, 2011

No. 49/UHC/Admin. A/2011--Smt. Geeta Chauhan, Civil Judge (J.D.), Dehradun is transferred & posted as Civil Judge (J.D.), Tanakpur, Distt. Champawat vice Ms. Meena Deopa.

March 10, 2011

No. 50/UHC/Admin. A/2011--Ms. Meena Deopa, Civil Judge (J.D.), Tanakpur, Distt. Champawat is transferred & posted as 1st Addl. Civil Judge (J.D.), Roorkee, Distt. Hardwar vice Sri Dharmendra Kumar Singh.

March 10, 2011

No. 51/UHC/Admin. A/2011--Ms. Rajni Shukla, 1st Addl. Civil Judge (J.D.), Hardwar is transferred & posted as Civil Judge (J.D.), Nainital vice Sri Vivek Srivastava.

March 10, 2011

No. 52/UHC/Admin. A/2011--Sri Vivek Srivastava, Civil Judge (J.D.), Nainital is transferred & posted as Civil Judge (J.D.), Narendra Nagar, Distt. Tehri Garhwal vice Smt. Manju Singh.

March 10, 2011

No. 53/UHC/Admin. A/2011--Sri Sudhir Kumar Singh, Civil Judge (J.D.), Vikasnagar, Distt. Dehradun is transferred & posted as Civil Judge (J.D.), Almora vice Sri Ritesh Kumar Srivastava.

March 10, 2011

No. 54/UHC/Admin. A/2011--Sri Udai Pratap Singh, Judicial Magistrate, Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar is transferred & posted as Civil Judge (J.D.), Tehri Garhwal vice Sri Ashutosh Kumar Mishra.

March 10, 2011

No. 55/UHC/Admin. A/2011--Sri Dharmendra Kumar Singh, 1st Addl. Civil Judge (J.D.), Roorkee, Distt. Hardwar is transferred & posted as Civil Judge (J.D.), Uttarkashi vice Sri Man Mohan Singh.

March 10, 2011

No. 56/UHC/Admin. A/2011--Sri Sudhir Tomar, 1st Addl. Civil Judge (J.D.), Udham Singh Nagar is transferred & posted as Civil Judge (J.D.), Pauri Garhwal vice Sri Arun Vohra.

March 10, 2011

No. 57/UHC/Admin. A/2011--Sri Man Mohan Singh, Civil Judge (J.D.), Uttarkashi is transferred & posted as 1st Addl. Civil Judge (J.D.), Udham Singh Nagar vice Sri Sudhir Tomar.

March 10, 2011

No. 58/UHC/Admin. A/2011--Sri Mukesh Chandra Arya, Judicial Magistrate, Roorkee, Distt. Hardwar shall be the 2nd Addl. Civil Judge (J.D.), Roorkee, Distt. Hardwar vice Smt. Sangeeta Rani.

March 10, 2011

No. 59/UHC/Admin. A/2011--Smt. Manju Singh, Civil Judge (J.D.), Narendra Nagar, Distt. Tehri Garhwal is transferred & posted as Civil Judge (J.D.), Gangolihat, Distt. Pithoragarh in the vacant Court.

March 10, 2011

No. 60/UHC/Admin. A/2011--Sri Ramesh Singh, Civil Judge (J.D.), Haldwani, Distt. Nainital is transferred & posted as Civil Judge (J.D.), Gopeshwar, Distt. Chamoli vice Sri Jayendra Singh.

March 10, 2011

No. 61/UHC/Admin. A/2011--Smt. Sangeeta Rani, 2nd Addl. Civil Judge (J.D.), Roorkee, Distt. Hardwar is transferred & posted as Civil Judge (J.D.), Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar vice Sri Chandramani Rai.

March 10, 2011

No. 62/UHC/Admin. A/2011--Sri Arun Vohra, Civil Judge (J.D.), Pauri Garhwal is transferred & posted as Addl. Civil Judge (J.D.), Khatima, Distt. Udham Singh Nagar vice Sri Pradeep Kumar Mani.

March 10, 2011

No. 63/UHC/Admin. A/2011--Mrs. Gajan Devi, 1st Addl. Civil Judge (J.D.), Haldwani, Distt. Nainital shall be the Civil Judge (J.D.), Haldwani, Distt. Nainital vice Sri Ramesh Singh.

March 10, 2011

No. 64/UHC/Admin. A/2011--Sri Jayendra Singh, Civil Judge (J.D.), Gopeshwar, Distt. Chamoli is transferred & posted as 1st Addl. Civil Judge (J.D.), Haldwani vice Mrs. Gajan Devi.

By Order of the Court,

Sd/-

U. C. DHYANI,
Registrar General..



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2011 ई0 (चैत्र 12, 1933 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पंचायती राज विभाग

10 दिसम्बर, 2010 ई0

सं0 518/23-5(5)(2009-10)-जिला पंचायत पौड़ी-गढ़वाल द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत पौड़ी-गढ़वाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदारी व्यवसाय/ठेकेदारी व्यवसाय को विनियमित करने सम्बन्धी पूर्व में शासकीय विज्ञप्ति सं0-1654/23-4(1)(97-98), दिनांक 12 सितम्बर, 1998 एवं 24 मार्च, 1990 ई0 के भाग-2, 27 जनवरी, 1990 ई0 सं0-2-514/23-39(89-90) द्वारा निर्मित उपविधियों में आंशिक संशोधित करते हुये संशोधित उपविधियां बनायी गई है।

अतएव अधिनियम की धारा-242(2) की अपेक्षानुसार आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उक्त संशोधित उपविधियों की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते हैं। यह उपविधियां उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारी व्यवसाय करने सम्बन्धी उपविधियां जो उ0प्र0 गजट 24 मार्च, 1990 ई0 के भाग-2, 27 जनवरी, 1990 ई0 सं0-2-514/23-39(89-90) में प्रकाशित

जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-239(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व पारित ग्रामीण क्षेत्र/क्षेत्रों में ठेकेदारी व्यवसाय करने की उपविधियों में निर्धारित ठेकेदारी लाइसेन्स शुल्क एवं सामान्य सुरक्षा शुल्क जो उ0प्र0 गजट 24 मार्च, 1990 ई0 (चैत्र 3, 1912 शक संवत्) के भाग-2, 27 जनवरी, 1990 ई0 सं0-2-514/23-39(89-90) में प्रकाशित है में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित उपविधि संशोधित की जाती है :-

वर्तमान उपविधि

3-लाइसेन्स शुल्क जिले के भीतर किसी भी विभाग में कार्य करने हेतु 200.00 (दो सौ रुपये) जमा करना होगा।

4-जो व्यक्ति समिति या फर्म आदि केवल जिला पंचायत में कार्य करना चाहे, उन्हें लाइसेन्स शुल्क के अतिरिक्त राष्ट्रीय बचत पत्रों के रूप में जो अपर मुख्य अधिकारी के पदनाम प्लेज्ड होंगे तथा लाइसेन्स की समाप्ति अथवा नवीनीकरण न करवाने की स्थिति में वापस किये जायेंगे। रु0 2,500.00 सामान्य सुरक्षा के रूप में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत निर्माण नियमावली के अनुसार पंजीकृत शुल्क अंकन 100.00 रु0 अलग जमा करना होगा।

संशोधन हेतु प्रस्तावित उपविधि

ठेकेदारी व्यवसाय करने के लिये जिले के भीतर किसी भी विभाग में जिला पंचायत को छोड़कर रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) जमा करने पर ठेकेदारी लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा।

श्रेणी	सामान्य जमानत धनराशि	हैसियत	कार्य की लागत	नवीनीकरण
A-प्रथम	20,000	5,00,000	सभी लागत के कार्य	1500
B-द्वितीय	15,000	3,00,000	4,00,000 तक	1000
C-तृतीय	5,000	50,000	1,00,000 तक	600

B और C श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार अपनी पंजीकरण सीमा से अधिक के कार्य/टेण्डर उसी दशा में ले सकेंगे जब उनके द्वारा अपनी पंजीयन का उच्चीकरण किया गया हो इसके लिये उन्हें प्रारम्भ में टेण्डर की सभी औपचारिकतायें पूर्ण करनी होगी।

A-श्रेणी के लिए अनुमोदित ठेकेदार को भवन/सड़क/पुल आदि निर्माण कार्य के विगत 3 वर्षों में 5-5 लाख के 4(चार) निर्माण कार्यों के निष्पादन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

B-श्रेणी के लिए भी A-श्रेणी की भांति 4(चार) लाख के निर्माण कार्यों के निष्पादन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान/व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धी उपविधियां

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (संशोधित 1994) की धारा 239(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बाजारों, कस्बों एवं किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की दुकान/व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह के कार्य को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के निमित्त पूर्व पारित उपविधियां जो उ0प्र0 शासकीय गजट सं0 1654/23-4(1) (97-98) दिनांक 12 सितम्बर, 1998 को प्रख्यापित है, को संशोधित करते हुए निम्नलिखित उपविधियां बनायी हैं, जो उत्तराखण्ड राज्य के गजट की तिथि से प्रभावी होगी :-

उपविधियां

1-कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म एवं समिति जनपद के ग्राम्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुकान, स्टोर नहीं कर सकेगा जब तक कि जिला पंचायत से निर्धारित शुल्क देकर लाइसेन्स प्राप्त न कर लिया हो।

2-कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की छूत की बीमारी से ग्रसित हो, किसी भी प्रकार की दुकान न कर सकेगा और ना ही किसी ऐसे रोगी को नौकर रख सकेगा।

3-कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म व समिति किसी नाबालिग को श्रमिक के रूप में नियुक्ति नहीं करेगा।

4-खाद्य पदार्थ रखने व बनाने हेतु किसी ऐसे धातु के बर्तनों का प्रयोग वर्जित होगा जिसमें खाद्य पदार्थ के विकृत या दूषित होने की सम्भावना हो या जिन पर रखा हुआ पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

5-खाद्य पदार्थ को इस प्रकार ढक कर रखा जायेगा ताकि उस पर धूल, मक्खियां या स्वास्थ्य के लिए अन्य हानिकारक जीवाणु न बैठ सकें।

6-प्रत्येक व्यवसायी को अपनी दुकान के ऐसे स्थान पर जो सुगमता से दिखायी दे सके एक साईन बोर्ड लगाना होगा जिस पर लाइसेन्सधारी का नाम व व्यवसाय का नाम स्पष्ट देवनागरी लिपि में लिखा होगा।

7-फैक्ट्रियों, भट्टों, क्रेसरों को पर्यावरण प्रदूषण का प्रमाण पत्र नियमानुसार उपलब्ध कराना होगा।

8-इन उपविधियों के अधीन अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी जिला पंचायत के लाइसेन्स अधिकारी होंगे।

9-पंचायत को अधिकार होगा कि वह इन उपविधियों के अधीन किसी विशेष क्षेत्र के लाइसेन्स शुल्क की उगाही ठेका देकर वसूल करने का निर्णय लें। ऐसी दशा में लाइसेन्स शुल्क की वसूली का ठेका आम बोली द्वारा अवधारित होगा। नीलामी अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, वित्त अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा की जायेगी। किन्तु ठेका को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जिला पंचायत में निहित होगा।

10-अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को इन उपविधियों के अधीन निर्गत किसी लाइसेन्स को लाइसेन्सधारी के द्वारा उपविधियों के उल्लंघन पर रद्द करने का अधिकार होगा किन्तु लाइसेन्सधारी लाइसेन्स रद्द किये जाने के 30 दिन के भीतर अध्यक्ष जिला पंचायत को अपील कर सकेगा। अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

11-पंचायत तथा राज्य सरकार के निम्नलिखित अधिकारी दुकान पर बिक्री हेतु रखी गयी सामग्री के निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होंगे तथा जनस्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक सामग्री को नष्ट कर सकेंगे :-

- (i) अध्यक्ष जिला पंचायत एवं पंचायत का कोई भी सदस्य जिसको अध्यक्ष द्वारा तदर्थ अधिकृत किया गया हो।
- (ii) मुख्य अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, वित्त अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी।
- (iii) जिले में कार्यरत जिला पूर्ति अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, उपमुख्य चिकित्साधिकारी अथवा जनस्वास्थ्य/खाद्यान्न विभाग का कोई अन्य अधिकारी जो स्वास्थ्य/खाद्य/खाद्यान्न निरीक्षक से कम दर्जे का नहीं।

12-प्रत्येक लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष की होगी जो 1 अप्रैल से अनुवर्ती वर्ष की 31 मार्च तक होगी। लाइसेन्सधारी का स्वयं का दायित्व होगा कि वह 30 जून तक अपने लाइसेन्स का नवीनीकरण करवा लें अन्यथा 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क उक्त तिथि के बाद लाइसेन्स शुल्क के अतिरिक्त लिया जायेगा।

13-इन उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से ठीक पूर्व व्यवसाय करने वाले व्यक्ति/संस्था/फर्म एवं समिति आदि को उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से 90 दिन के भीतर लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

14-इन उपविधियों के अधीन लाइसेन्स शुल्क की दरें निम्न प्रकार से होंगी :-

क्र0सं0	संशोधित उपविधियां	शुल्क की वर्तमान दरें	शुल्क की प्रस्तावित दरें
1	2	3	4
1.	प्रत्येक कपड़ा, परचून आदि की सम्मिलित दुकान पर	50	150
2.	केवल कपड़ा या परचून की दुकान पर	75	100
3.	प्रत्येक चाय एवं हलवाई की सम्मिलित दुकान पर	75	150
4.	केवल होटल, भोजनालय पर	75	100
5.	केवल चाय की दुकान पर (खोका)	50	60
6.	होटल जहां पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था हो-		
	क-जहां दस यात्री तक ठहरते हों (10 शैया)	75	150
	ख-जहां बीस यात्री तक ठहरते हों (20 शैया)		200
	ग-जहां बीस से अधिक यात्रियों को ठहराने की आधुनिक व्यवस्था हो		300

1	2	3	4
	घ-होटल, जिसमें खेल उपकरण झूला, चर्खी, स्विमिंग पूल, बोट आदि की व्यवस्था हो		1000
	ङ-तीन सितारा एवं पांच सितारा होटल		2000
7.	क-डाक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हों	75	150
	ख-डाक्टर के साथ नर्सिंग होम भी चलाते हों	200	250
	ग-मेडिकल स्टोर/कैमिस्ट की दुकान	75	150
8.	नाई, धोबी, मोची की दुकान-		
	क-नाई, धोबी, मोची जो सड़क पर ठेली लगाकर कार्य करते हों	50	60
	ख-नाई, धोबी, मोची जो पक्की दुकान पर कार्य करते हों	50	75
	ग-धोबी/ड्राईक्लीनर जो मशीन से कार्य करते हों	50	100
9.	क-फोटोग्राफर की दुकान	50	100
	ख-फोटोग्राफर जो वीडियोग्राफी का कार्य करते हों		125
	ग-फोटोग्राफर जो पर्यटक/धार्मिक स्थलों पर फोटोग्राफर का कार्य करते हों	50	150
10.	क-फोटोस्टेट की दुकान पर	50	75
	ख-टाईपिंग/कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट पर	75	150
11.	पान, बीड़ी/सिगरेट की दुकान पर	50	75
12.	पुस्तक, कॉपी/पत्रिका की दुकान पर	50	75
13.	क-बिसातखाना/जनरल स्टोर की दुकान पर	75	100
	ख-जूते, चप्पल की दुकान पर	50	100
14.	सब्जी, फल, फूल की दुकान पर	50	100
15.	लोहार तथा बर्तन मरम्मत की दुकान पर	50	75
16.	क-सरिया, सीमेन्ट की दुकान पर	75	200
	ख-क्रेषर प्लांट उद्योग पर	200	750
17.	बोतल, स्टेनलेस स्टील, ताबाँ सब्बल, घन, कील, रैक आदि की दुकान पर	75	150
18.	भवन निर्माण सामग्री की सम्मिलित दुकान पर	200	250
19.	ईंट, जाली निर्माण व्यवसाय पर	200	250
20.	सोने, चांदी के आभूषण व दुकान	75	150
21.	पेट्रोल पम्प एवं डीजल पम्प या इस प्रकार के अन्य व्यवसाय पर	200	500
22.	मिट्टी तेल की दुकानें, ग्रेड डीलर पर	75	80
23.	गैस सिलेण्डर, चूल्हे की दुकान पर	75	200
24.	क-साईकिल मरम्मत की दुकान पर	50	75
	ख-टायर पंचर, हवा भरना, ग्रीश आदि का कार्य	50	100
	ग-स्कूटर, मोटर साईकिल की मरम्मत का कार्य	50	200
	घ-सभी प्रकार की गाड़ी मरम्मत (वर्कशॉप)	75	500
	ङ-गैस वैल्विंग, फ़ैब्रीकेशन, ग्रिल, रेलिंग आदि का कार्य	75	300
	च-बैटरी मरम्मत की दुकान	50	100

1	2	3	4
25.	क-विद्युत सामान की दुकान पर ख-रेडियो, टी0वी0, डिस्क, मोबाइल, सी0डी0, पंखा, फ्रिज, वाशिंग मशीन, प्रेस, दुल्लू पम्प, आदि की मरम्मत की दुकान पर ग-घड़ीसाज की दुकान पर घ-चश्में/आप्टीकल्स की दुकान पर	75 75 75 75	150 500 100 100
26.	कारतूस/बारूद की दुकान पर	100	300
27.	फर्नीचर की दुकान पर	75	200
28.	प्रिंटिंग प्रेस पर	100	200
29.	कताई, बुनाई, हथकरघा, लघु उद्योग पर	75	200
30.	सरिया, स्टील फैक्ट्री पर	200	1000
31.	क-सिनेमाघर ख-वीडियोहाल (मनोरंजन गृह)	200 100	1000 500
32.	क-बैडिंग प्लांट (बारातघर पक्का) ख-टैन्ट हाउस कच्चा	200 100	1000 500
33.	टेलर मास्टर जो अकेला कार्य करता हो	50	75
34.	टेलर मास्टर जिसकी दुकान पर तीन कारीगर कार्य करते हों	50	125
35.	टेलर मास्टर जिसकी दुकान पर तीन से अधिक कारीगर कार्य करते हों	50	200
36.	जो कम्पनी एवं निगम/उपक्रम, मोबाइल टावर, दूरसंचार आदि लगाती हो	200	2000
37.	क-ग्रामीण क्षेत्रों में माल ढोने वाले गधे, घोड़े एवं खच्चरों पर (प्रति पशु) ख-ग्रामीण क्षेत्रों से असहाय पशुओं को मैदानी क्षेत्रों में बाह्य जनपदों में ले जाने पर पंजीकरण शुल्क (प्रति पशु)	50 50	60 100
38.	ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी व्यवसाय करने पर	50	300
39.	क-पावर चक्की, आटा एवं मसाला ख-पावर चक्की जिसमें आटा, धान, मसाला/कोल्हू, रुई तथा आरा मशीन का कार्य	75 75	200 250
40.	क-बेकरी उद्योग जिसका मासिक उत्पादन 5 किंवटल तक होता है ख-बेकरी उद्योग जिसका मासिक उत्पादन 5 किंवटल से अधिक होता है	75 75	250 500
41.	साबुन उद्योग का कार्य करने पर	200	500
42.	मोमबत्ती का कार्य करने पर	200	500
43.	प्लास्टिक उद्योग का कार्य करने पर	200	500
44.	धूप/अगरबत्ती खुशबूदार आदि वस्तुओं के निर्माण/उद्योग पर	200	500
45.	प्रापर्टी डीलर एवं एजेंट पर	200	2000
46.	ग्रामीण क्षेत्रों में कबाड़ी का कार्य करने पर	50	500
47.	ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले दैनिक/पाक्षिक मेलों अथवा उत्सवों पर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों पर- क-मिठाई/चाय की दुकान पर	50	60

1	2	3	4
	ख-श्रृंगार एवं चूड़ी की दुकान पर	50	60
	ग-शाल/साफे, कपड़े आदि की दुकान पर	50	60
	घ-कोल्ड-ड्रिंक, आइसक्रीम, गुब्बारे आदि खिलौनों पर	50	60
	ङ-चर्खी छोटी आदि पर	50	100
	च-चर्खी बड़ी आदि पर	50	200
	छ-सर्कस आदि पर	200	500
48.	क-देशी शराब आदि की दुकान पर	200	500
	ख-विदेशी/अंग्रेजी शराब आदि की दुकान पर	200	1000

शास्ति

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर रु0 1000.00 तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनमें उल्लंघन जारी रहा हो रु0 50.00 प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर 3 मास के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

केशर सिंह नेगी,
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल।

जयेन्द्रसिंह पंवार,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल।

अजय सिंह नबियाल,
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2011 ई0 (चैत्र 12, 1933 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पंचायत, हरबर्टपुर, देहरादून

सूचना

03 मार्च, 2011 ई0

सं0 848 पॉलीथीन गजट/2010-11-नगर पंचायत, हरबर्टपुर (देहरादून) ने यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट 1916 (यथा संशोधित) की धारा 298 (1) (एक) की सूची-1 शीर्षक 'ज' के खण्ड ज (ड) के अधीन अपनी सीमान्तर्गत नगर को स्वच्छ बनाये रखने, मानव जीवन तथा पशुजीवन, पर्यावरण तथा प्रदुषण की रक्षा, लोक सुरक्षा या सुविधा में अभिवृद्धि की दृष्टि में पॉलीथीन/कैरीबैग या इसी प्रकार की अन्य पॉलीथीन सामग्री जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हो, को नियन्त्रित व प्रतिबन्धित करने हेतु उपविधियों की प्रस्तावना की गयी है जो समस्त प्रभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से प्रकाशित किये गये थे। निर्धारित समय अन्तर्गत कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुये। तैयार उपनियमों का अनुमोदन बोर्ड प्रस्ताव सं0 150 दिनांक 15-02-2011 के द्वारा किया गया है। अतः नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा (298) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त उपविधियों का उत्तराखण्ड शासकीय साधारण गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू किये जाने की स्वीकृति की जाती है।

उपविधि

1-संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना-

- (1) यह उपविधि नगर पंचायत, हरबर्टपुर पॉलीथीन/कैरीबैग नियंत्रण उपविधि-2010 कहलायेगी।
- (2) यह नगर पंचायत हरबर्टपुर की सीमान्तर्गत प्रवृत्त होगी।
- (3) यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2-परिभाषाये-

- (1) जब तक इस विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में।
- (क) ऐक्ट का तात्पर्य उत्तराखण्ड नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यथा संशोधित) से है।
- (ख) नगर पालिका परिषद् से तात्पर्य नगर पंचायत हरबर्टपुर (देहरादून से है)।
- (ग) पालिका सीमा क्षेत्र का तात्पर्य उस सीमा क्षेत्र से है जो कि शासकीय गजट संख्या 3821-टी/9-1-84-1-टी0-71 लखनऊ, दिनांक 29 अगस्त, 1984 के द्वारा अधिसूचित किया गया है में प्रकाशित सीमाओं से है।
- (घ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत हरबर्टपुर (देहरादून) के अधिशासी अधिकारी से है।
- (ङ) सफाई निरीक्षक का तात्पर्य नगर पंचायत हरबर्टपुर के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक से है।
- (च) अध्यक्ष का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो हरबर्टपुर नगर पंचायत बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया हो।
- (छ) पालिका बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत, हरबर्टपुर के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी तथा ऐसी कमेटी के भंग हो जाने की स्थिति में प्रशासन या उनके द्वारा प्रतिनिधित्वित व्यक्ति से है।

प्रतिषेध-

3-कोई भी व्यक्ति व्यवसायी या दुकानदार नगर पंचायत हरबर्टपुर की सीमा के अन्तर्गत किसी प्रकार के पॉलीथीन/कैरीबैग का भण्डारण, उत्पादन, बिक्री और परिवहन नहीं करेगा न ही बिक्री हेतु लायेगा।

4-पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी या दुकानदार किसी भी प्रकार का पॉलीथीन कैरीबैग या अन्य प्रकार की ऐसी कोई पॉलीथीन क्रय/विक्रय नहीं करेगा और न ही बेचने की चेष्टा करेगा। जिससे पर्यावरण को क्षति हो, प्रदूषण पैदा हो तथा नगर में गन्दगी होने की सम्भावना हो।

5-पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्थान/सार्वजनिक स्थान जैसे नदी/भूमि/नाली/मकान/आंगन/बगीचा/शौचालय/मूत्रालय/दुकान के आगे-पीछे ऐसी पॉलीथीन कैरीबैग अनुपयोगी प्लास्टिक के डिब्बे चायपत्ती के खाली रैपर्स/गुटकों के खाली रैपर्स जैसी अनुपयोगी वस्तुओं को नहीं रखेगा/फेंकेगा जिससे पर्यावरण को क्षति हो, प्रदूषण उत्पन्न हो, जो मानव जीवन पशु जीवन के लिये घातक हो तथा जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हो।

6-पालिका क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सामान की पैकिंग्स पर आने वाला पॉलीथीन/गत्ता/चिल्ला जो भी हो, क्रेता/विक्रेता अपने घर/दुकान में एक बर्तन में एकत्र कर रखेगा तथा पालिका से सफाई कर्मियों को उसकी ड्यूटी के दौरान उसके सुपुर्द करेगा, जिसे ठोस अपशिष्ट (प्रबन्ध व हथालन) नियम, 2000 के अनुसार पालिका द्वारा निस्तारित किया जायेगा।

7-सीमेन्ट के खाली बैग जो पॉली पैक में आते हो जैसे रबर किस चिल्ला चाय पत्ती की थैली रैपर्स (टैट्रापेक) पराग दूध या इसी प्रकार दूध के अन्य रैपर्स, बिस्कुट पैकेट के पॉली पैक रैपर्स/खाली डिब्बे विभिन्न प्रकार के तम्बाकू/गुटकों आदि समस्त प्रकार के प्लास्टिक पैक रैपर्स, जो अनुपयोगी हो जाते हैं को ऐसे सामान का क्रेता/विक्रेता/मालिक या तो अपनी सुरक्षा में रखेगा या अपने घर/दुकान में एक बर्तन में एकत्र कर रखेगा जिसे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पालिका के सफाई कर्मचारी को उसकी ड्यूटी के समय दिया जायेगा, जिसे पालिका द्वारा उपनियम 6 में उल्लिखित विधि से निस्तारित किया जायेगा।

8-पालिका सीमान्तर्गत प्रवेश/गुजरने वाले कोई भी वाहन चालक/यात्री नगर की सीमा में पॉलीथीन की थैली/कैरीबैग/पैकेट/डिब्बे/रैपर्स जो कि पॉलीथीन की श्रेणी में हो और जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हो पालिका की सड़कों/गलियों या खुले स्थान/सार्वजनिक स्थान में नहीं फेंकेगा, बल्कि पालिका के डस्टबिन/कन्टेनर में ही डाल सकेगा।

9-पालिका सीमान्तर्गत जिस किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों भवन स्वामियों/किरायेदारों, कुलियों मजदूरों के अगल-बगल जिसकी सीमान्तर्गत ऐसी पॉलीथीन/कैरीबैग या अन्य प्रकार का पॉलबैग जैसे पराग दूध के अनुपयोग रैपर्स या इसी प्रकार के अन्य अनुपयोगी पॉलीबैग सामग्री जिससे गन्दगी उत्पन्न हो और होने की सम्भावना हो, वह दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत माना जायेगा।

शास्ति

1-जो कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों/व्यवसायी/दुकानदार या कम्पनियों द्वारा इस उपविधि के किसी अंश या उसके तहत जारी आदेशों का उल्लंघन किया जायेगा वह रु0 5000/- (पांच हजार रुपये) जुर्माने अथवा 01 माह के कारावास अथवा दोनों से दण्डनीय होगा और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहता है तो वह रु0 100/- प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त दण्डित होगा।

2-जो कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी दुकानदार इस उपविधि के अधीन किसी भी रीति से अपराध करने अपराध में सहायता, दुष्प्रेरण करता है, या उपसाधक है, वह दोष सिद्ध होने पर अपराध के लिये चिन्हित कारावास से दण्डित किया जायेगा।

3-नगर पंचायत हरबर्टपुर के अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पालिका के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अधिकार होगा कि वह इस प्रकार के अपराधों के लिये तात्कालिक रूप से रु0 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) तक नगद रूप से अर्थदण्ड ले सकते हैं।

ह0/- अपठित,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, हरबर्टपुर,
देहरादून।

ह0/- अपठित,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, हरबर्टपुर,
देहरादून।